कुछ विशिष्ट नशीले पदार्थों और चोरी के अपराधों के लिए घोर अपराधों के आरोप लगाने की अनुमति देता है और सज़ाओं को बढ़ाता है। पहल विधान।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश

अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार किया गया

इस विधेयक का टेक्स्ट पृष्ठ 127 और राज्य सचिव की वेबसाइट voterguide.sos.ca.gov पर देखा जा सकता है।

- नशीले पदार्थों की पूर्व में दो या चोरी की पूर्व में दो दोषसिद्धियों के साथ, जैसा भी लागू होता है—अपने पास कछ विशिष्ट नशीले पदार्थ रखने और \$950 से कम की चोरियों के लिए घोर अपराध के आरोप लगाने की अनुमति देता है-जिन दोनों के लिए इस समय छोटे अपराध होने का आरोप लगाया जाता है। जो प्रतिवादी नशीले पदार्थ रखने के घोर अपराध को स्वीकार करते हैं और उपचार को पूरा करते हैं, उन पर लगे आरोप खारिज किए जा सकते हैं।
- नशीले पदार्थ और चोरी के अन्य विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए सज़ाओं को बढाता है।
- जेल की बढ़ी हुई सज़ाओं से वे बचतें कम हो सकती हैं जो इस समय मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थ के उपचार प्रोग्रामों, K-12 स्कूलों, और अपराध पीड़ितों के लिए निधिकरण करती हैं; किसी भी शेष बचत का नए घोर अपराध उपचार प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- मुख्य रूप से जेल की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, बढ़ी हुई राज्य आपराधिक न्याय लागतों के वार्षिक रूप से कई दिसयों मिलियन डॉलर से लेकर अल्प सैंकड़ों मिलियन डॉलर तक होने की संभावना है।
- मुख्य रूप से काउंटी जेल, सामुदायिक निरीक्षण, और न्यायालय द्वारा अनिवार्य बनाए गए मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थ के उपचार के कार्यभार के कारण बढी हुई स्थानीय आपराधिक न्याय लागतों के वार्षिक रूप से दिसयों मिलियन डॉलर होने की संभावना है।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

परिप्रेक्ष्य

सजा अपराध की गंभीरता और आपराधिक इतिहास पर निर्भर करती है

घोर अपराधों के लिए सज़ा। घोर अपराध सबसे गंभीर प्रकार का अपराध होता है। लोगों को अपराध और उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर घोर अपराधों के लिए काउंटी जेल या राज्य कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। कुछ मामलों में, लोगों को जेल या कारावास में उनको सुनाई गई सज़ा का कुछ या पूरा समय गुजारने के बजाय, काउंटी परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा समुदाय में ही उन पर निरीक्षण रखा जा सकता है। इसे ही काउंटी सामुदायिक निरीक्षण कहा जाता है। अधिकांशतः सज़ा की अवधि अपराध पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, हत्या के लिए 15 साल या उससे अधिक की जेल की सज़ा हो

सकती है। इसके विपरीत, नशे की बिक्री पर नशीले पदार्थ के आधार पर पांच साल तक की जेल या कारावास की सज़ा हो सकती है। अपराध के विवरणों के कारण सज़ाएँ बढ़ाई भी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नशों (जैसे फेंटानिल, हेरोइन, कोकीन, या मेथामफेटामीन) को बेचने की सज़ा उसकी बेची गई माता के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

छोटे अपराधों के लिए सज़ा। छोटा अपराध कम गंभीरता वाला अपराध होता है। इसके उदाहरणों में हमला करना और अपने पास नशा रखना शामिल हैं। लोगों को छोटे अपराधों के लिए काउंटी जेल, काउंटी सामुदायिक निरीक्षण और/या जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। एक साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है।

36

प्रस्ताव 47 चोरी और नशा संबंधी कुछ अपराधों के लिए सज़ाओं में कमी

2014 में, प्रस्ताव 47 ने चोरी और नशा संबंधी अपराधों को घोर अपराधों से बदलकर छोटे अपराधों की श्रेणी में डाल दिया। उदाहरण के लिए, दुकान से चोरी करना (दुकान से \$950 या उससे कम मूल्य वाली वस्तुएँ चुराना) और नशा अपने पास रखना आमतौर पर छोटे अपराध बन गए।

प्रस्ताव

प्रस्ताव 36 चोरी और नशा संबंधी अपराधों के लिए सज़ाओं से संबंधित कई मुख्य बदलाव करता है। पहला, इनमें से कुछ अपराधों के लिए यह सज़ा को बढ़ा देता है। दुसरा, यह अपने पास नशा रखने संबंधी कुछ अपराधों के लिए एक नई उपचार-केंद्रित अदालती प्रक्रिया निर्मित करता है। तीसरा, इसमें अदालतों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अवैध नशा बेचने या उपलब्ध कराने के दोषी लोगों को चेतावनी दें कि यदि वे ऐसा करते रहे और इससे किसी की मौत हो गई तो उन पर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है।

चोरी और नशा संबंधी अपराधों के लिए सज़ा को बढ़ाता है

प्रस्ताव 36 चोरी और नशा संबंधी अपराधों के लिए सज़ा को तीन तरह से बढ़ाता है:

• कुछ छोटे अपराधों को घोर अपराधों में बदल देता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में \$950 या उससे कम मूल्य की वस्तुओं की चोरी छोटे अपराध में आती है। प्रस्ताव 36 इस अपराध को घोर अपराध बना देता है यदि व्यक्ति को चोरी के कुछ अपराधों (जैसे दुकान से चोरी, सेंधमारी, या कार छीनना) के लिए पहले ही दो या इससे अधिक बार दोषी ठहराया जा चुका है। इसकी सज़ा काउंटी जेल या राज्य कारावास

में तीन साल तक की होगी। ये बदलाव प्रस्ताव संख्या 47 में सज़ाओं की कुछ कटौतियों को पूर्ववत कर देते हैं।

- घोर अपराधों के लिए कुछ सज़ाओं को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, प्रस्ताव 36 चोरी या संपत्ति की क्षित के लिए घोर अपराध की सजा को तीन साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है यदि यह अपराध तीन या इससे अधिक लोगों ने एक साथ किया हो।
- कुछ घोर अपराधों के लिए कारावास में सज़ा काटना आवश्यक बनाता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कुछ नशों (जैसे फेंटानिल, हेरोइन, कोकीन, या मेथामफेटामीन) को बेचने की सज़ा उसकी बेची गई माला के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में, व्यक्ति के आपराधिक इतिहास के आधार पर ये सज़ाएँ काउंटी जेल या राज्य कारावास में काटी जाती हैं। प्रस्ताव 36 इन सज़ाओं को कारावास में काटना आवश्यक बनाता है।

अपने पास नशा रखने संबंधी कुछ अपराधों के लिए नई अदालती प्रक्रिया निर्मित करता है

प्रस्ताव 36 कुछ मामलों में, अपने पास अवैध नशा रखने वाले लोगों पर छोटे अपराध के बजाय "उपचार-अनिवार्य अपराध" का आरोप लगाने की अनुमति देता है। खासतौर पर, यह उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें अतीत में (1) अपने पास कुछ नशे (जैसे कि फेंटानिल, हेरोइन, कोकीन, या मेथामफेटामीन) रखने और (2) नशे संबंधी कुछ अपराधों (जैसे अपने पास नशा रखना या उसे बेचना) के लिए दो या इससे ज़्यादा बार दोषी ठहराया जा चुका है। इन लोगों को आमतौर पर ऐसे उपचार प्राप्त होंगे, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य या नशे संबंधी उपचार। जो उपचार को पूरा कर लेंगे, उनके आरोप खारिज कर दिए जाएंगे। जो उपचार पूरा नहीं करते, उन्हें राज्य कारावास में तीन

36

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी है

साल तक की सज़ा काटनी पड़ सकती है। यह बदलाव प्रस्ताव 47 में सज़ाओं की कुछ कटौतियों को पूर्ववत कर देता है।

नशा बेचने या उपलब्ध कराने पर संभावित हत्या के आरोपों की चेतावनी देना आवश्यक बनाता है

प्रस्ताव 36 न्यायालयों के लिए लोगों को यह चेतावनी देना आवश्यक बनाता है कि यदि वे किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार अवैध नशीले पदार्थ बेचते या उपलब्ध कराते हैं तो उन पर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है। यह चेतावनी उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कुछ खास नशीले पदार्थों (जैसे फेंटानिल, हेरोइन, कोकीन और मेथामफेटामीन) को बेचने या उपलब्ध कराने का दोषी ठहराया गया है। इससे यह संभावना बढ़ सकती है कि यदि वे बाद में भी किसी व्यक्ति को अवैध नशीले पदार्थ बेचते या उपलब्ध कराते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें हत्या का दोषी ठहराया जाएगा।

राजकोषीय प्रभाव

प्रस्ताव 36 के राज्य और स्थानीय सरकारों पर विभिन्न राजकोषीय प्रभाव होंगे। इन प्रभावों का आकार अनिश्चित कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि स्थानीय अभियोक्ता क्या निर्णय लेंगे।

राज्य की आपराधिक न्याय लागतें बढ़ा देता है। प्रस्ताव 36 दो मुख्य तरीकों से आपराधिक न्याय लागतें बढ़ा देगा।

 राज्य जेल की आबादी में बढ़ोत्तरी। इसके तहत अभी काउंटी स्तर पर अपनी सजा काट रहे कुछ लोगों के लिए आवश्यक होगा, वे राज्य की जेल में अपनी सजा काटें। इसके अलावा, यह जेल की कुछ सज़ाओं को बढ़ा देता है। कुल मिलाकर, जेल की आबादी लगभग कुछ हजार लोगों तक बढ़ सकती है। (अभी जेल में लगभग 90,000 लोग हैं।) राज्य न्यायालय के कार्यभार में बढ़ोत्तरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि घोर अपराधों को सुलझाने में आमतौर पर छोटे अपराधों के मुकाबले ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा, उपचार-अनिवार्य अपराध न्यायालय का कार्यभार बढ़ा देंगे।

कुल मिलाकर, प्रस्ताव 36 राज्य की आपराधिक न्याय लागतों को बढ़ा देगा, जो कि प्रत्येक वर्ष (वार्षिक रूप से) ऊपर में दिसयों मिलियन डॉलर से लेकर कम से कम सैकड़ों मिलियन डॉलर तक हो सकती हैं। यह राशि राज्य के मौजूदा सामान्य निधि बजट के 1 प्रतिशत के आधे से भी कम है। (सामान्य कोष वह खाता है जिसका इस्तेमाल राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जेलों सहित अधिकांश सार्वजिनक सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाता है।) स्थानीय आपराधिक न्याय लागतें बढ़ा देता है। प्रस्ताव 36 दो मुख्य तरीकों से स्थानीय आपराधिक न्याय लागतें

बढा देगा।

- काउंटी जेल और सामुदायिक निरीक्षण वाली आबादी में शुद्ध वृद्धि। कुछ मायनों में, प्रस्ताव 36 जेल और सामुदायिक निरीक्षण वाली आबादी में कमी लाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग काउंटी स्तर के बजाय राज्य की जेल में जाएंगे। कुछ दूसरे मायनों में, यह इस आबादी को बढ़ा देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग काउंटी जेल में या सामुदायिक निरीक्षण में ज़्यादा समय बिताएंगे। कुल मिलाकर, प्रस्ताव 36 संभावित रूप से काउंटी की आबादी बढ़ा देगा। यह बढ़ोत्तरी लगभग कुछ हजार लोगों की हो सकती है। (काउंटी स्तर पर अभी लगभग 250,000 लोग हैं।)
- स्थानीय न्यायालय संबंधी कार्यभार में बढ़ोत्तरी। यह स्थानीय अभियोक्ताओं और सार्वजनिक वकीलों पर कार्यभार भी बढ़ा देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि घोर

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

अपराधों को सुलझाने में आमतौर पर छोटे अपराधों के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा, उपचार-अनिवार्य अपराध कुछ काउंटी एजेंसियों (जैसे परिवीक्षा या स्वभावजन्य स्वास्थ्य विभागों) के लिए कार्यभार उत्पन्न करेंगे।

कुल मिलाकर, प्रस्ताव 36 स्थानीय आपराधिक न्याय लागतों को बढ़ा देगा, जिसके सालाना दिसयों मिलियन डॉलर तक होने की संभावना है।

कुछ सेवाओं पर राज्य द्वारा आवश्यक रूप से खर्च की जाने वाली राशि घटा देता है। प्रस्ताव 47 ने एक ऐसी प्रक्रिया निर्मित की है जिसमें सज़ा में कटौतियों से राज्य की अनुमानित बचत को आवश्यक रूप से मानसिक स्वास्थ्य और नशे संबंधी उपचार, स्कूल अनुपस्थिति और स्कूल ड्रॉपआउट की रोकथाम और पीड़ित सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। पिछले साल के लिए कुल अनुमानित बचतें \$95 मिलियन की थीं। प्रस्ताव 47 के कुछ हिस्सों को पूर्ववत करके, प्रस्ताव 36, प्रस्ताव 47 से होने वाले राज्य की बचतों को घटा देता है। इससे राज्य द्वारा आवश्यक रूप से मानसिक स्वास्थ्य और नशे संबंधी उपचार, स्कूल

अनुपस्थिति और स्कूल ड्रॉपआउट रोकथाम और पीड़ित सेवाओं पर खर्च की जाने वाली राशि में कमी आएगी। यह कमी कम से कम दसियों मिलियन डॉलर सालाना की होगी। अन्य राजकोषीय प्रभाव। प्रस्ताव 36 के राज्य और स्थानीय सरकारों पर अन्य राजकोषीय प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बढ़ी हुई सज़ाओं या अनिवार्य उपचार से अपराध में कमी आती है, तो राज्य और स्थानीय आपराधिक न्याय की कुछ लागतों से बचा जा सकता है। हालाँकि, इसका पता नहीं है कि ये या अन्य प्रभाव होंगे अथवा नहीं।

मुख्य रूप से इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए गठित समितियों की सूची के लिए sos.ca.gov/ campaign-lobbying/cal-access-resources/ measure-contributions/2024-ballot-measurecontribution-totals पर जाएँ।

समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html पर जाएँ।

36